



दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

पीएम नरेन्द्र मोदी ने जनगणना को बताया राष्ट्रीय जिम्मेदारी, ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने की अपील की

नयी दिल्ली २७/०९
(संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनगणना को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए नागरिकों से अपनी की वीबे ऑनलाइन खुद अपनी जानकारी दर्ज करें, ताकि देश के भविष्य की योजना बनाने के लिए सटीक आंकड़े सुनिश्चित किए जा सकें। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में उन्होंने बताया कि अब तक 2.6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोबाइल फोन के जरिये जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज करके स्व-गणना प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्होंने कहा, "जनगणना हम सभी के लिए एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। यह देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके और आपके परिवार के बारे में सही जानकारी देश के भविष्य की सटीक तस्वीर बनाने में मदद करती है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन स्व-पंजीकरण सेवा बहुत सुविधाजनक है, जिससे नागरिक अपने और अपने



परिवार के बारे में जानकारी सिधे अपने मोबाइल फोन से आसानी से दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी के अलावा, यह सुविधा 16 क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा, देश की एक भव्य तस्वीर उभर रही है। इस तस्वीर में आप, आपका परिवार और आपके पड़ोसी भी शामिल हैं। मैं भारत की जनगणना की बात कर रहा हूँ। इस प्रक्रिया का पहला चरण सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में लगभग पूरा हो चुका है। मोदी ने कहा कि 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उज्जराखंड के

दूर-दराज, बर्फ से ढके इलाकों में अभी काम चल रहा है। उन्होंने कहा, इसके लिए आपको जनगणना पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। आपने मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉग-इन करें, अपनी लोकेशन डालें, अपने परिवार के बारे में जानकारी भरें और जानकारी दाखिल करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं और इसके लिए कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जानकारी जमा करने के बाद आपको एक खास आईडी मिलेगी। जब जनगणना करने वाला कर्मचारी आपके घर आए, तो आप यह आईडी उन्हें

दिखा सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद, यह जनगणना रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी।¹⁵ प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो प्रसारण में पर्यावरण और जानवरों की सुरक्षा के बारे में भी बात की। मोदी ने कहा कि जब लोग पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो वे सिर्फ पेड़-पौधों या जानवरों को ही नहीं बचाते, बल्कि पूरे परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही कुछ पहल इस भावना को बहुत खूबसूरती से उजागर कर रही हैं। असम के सोनाई रूपई वन्यजीव अभयारण्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब इस इलाके में हाथी रहते थे, लेकिन जैसे-जैसे वन भूमि पर इंसानी दखल बढ़ा, हाथी वहां से चले गए। उन्होंने कहा कि तीन साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था और इसके नीचे बहुत अच्छे रहे हैं— हाथी यहां वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा, हाथियों के झुंड फिर से

उन इलाकों में देखे जा रहे हैं, जहाँ वे कई साल से दिखते नहीं थे। खेलों के लिए प्रतिभा खोज अभियान के बारे में लाल किले से की गई अपनी घोषणा का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पंजाब में हॉकी खिलाड़ी राजिंदर सिंह सराहनीय काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके नाम के साथ 'सीनियर' शब्द जुड़ा है और वह उस टीम का हिस्सा थे, जिसने 1980 के ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। अब वे 'राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी' के जरिये अपनेपुनर्जुनून को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी कोशिशों से गांवों में हॉकी के लिए नये एस्ट्रो-टर्फ लगाए जा रहे हैं। राजिंदर जी का मनसुब बिल्कुल साफ है- ऐसे गांवों के बच्चों की पहचान करना, जहाँ अच्छी कोचिंग की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने सिंह की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा, “ऐसी पहल के जरिये, कई खिलाड़ी स्तर पर जूनियर और सीनियर भारत पर जगह बना रहे हैं।

कोलकाता २७/०९
(संवाददाता): पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्द्रु अधिकारी ने रविवार को आरोप लगाया कि राज्य विधानसभा चुनाव में हार के बाद हताश विपक्षी दल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर उनका विरोध "राजनैतिक से प्रेरित" है। अधिकारी ने एस संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि कुछ समाचार संगठन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत को "अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं" तथा वे "अफवाहें फैला रहे हैं।" उन्होंने निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की आलोचना को लेकर विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और दावा किया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से तथा सभी पक्षों की उचित भागीदारी के साथ की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, "बंगाल में हार के बाद हताश विपक्षी दल एसआईआर को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं।" केरलम से तुलना करते हुए



अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस वहां एसआईआर का समर्थन कर रही है क्योंकि उसने इस दक्षिणी राज्य में चुनाव जीता है, जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद पार्टी इस प्रक्रिया का विरोध कर रही है।

उन्होंने कहा, “चूंकि कांग्रेस ने केरल में चुनाव जीता है, इसलिए पार्टी वहां एसआईआर का समर्थन कर रही है, लेकिन बंगाल में इसका विरोध कर रही है क्योंकि कांग्रेस और उसके सहयोगी यहां चुनाव हार गए।” अधिकारी ने यह भी दावा किया, “बंगाल में एसआईआर के दौरान 27 लाख नाम हटाए जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार थीं, भाजपा या निर्वाचन आयोग

नहीं।" भाजपा नेता ने निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया के विरोध को लेकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद उनकी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) अब "एक ही सुर में बोल रही हैं।" अधिकारी ने वाम मोर्चा के शासनकाल से जुड़े राजनीतिक हिंसा के मामलों का भी जिक्र किया, जिनमें साईबाड़ी और नंदीग्राम की घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और माकपा के बीच कथित राजनीतिक समझौते को लेकर भी सवाल उठाया।

राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर भ्रम फैलाने के लिए पद से दंड इस्तीफा-मोहन यादव

भोपाल २७/०९
 (संवाददाता): मध्यप्रदेश के
 मुख्यमंत्री मोहन यादव ने
 मतदाता सूची के विशेष गहन
 पुनरीक्षण (एसआईआर) को
 लेकर जारी राजनीतिक विवाद
 के बीच रविवार को लोकसभा
 में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर
 झूठ बोलने व भ्रम फैलाने का
 आरोप लगाते हुए कहा कि इस
 “निंदनीय कृत्य” के लिए उन्हें
 अपने पद से इस्तीफा देना
 चाहिए। यादव ने प्रदेश
 मुज्यालय में भारतीय जनता
 पार्टी (भाजपा) की प्रदेश इकाई
 के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के
 साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन
 को संबोधित करते हुए मुख्य
 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार
 और निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर
 सिंह संधू व विवेक जोशी की



बैठक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बैठक और उसके बाद जारी बयान के बाद निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं रह गया। यादव ने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि मुख्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर से संबंधित फैसले एकतरफा नहीं लिए थे।

मुज्यमत्रि ने कहा, “राहुल गांधी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए और पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी कांग्रेस को भी देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी को इस तरह के व्यवहार से रोकना चाहिए।” उन्होंने कहा, “कांग्रेस सच्चा से बाहर रहने के कारण बौखलाई

हुई है, इसलिए वह लगातार निंदनीय कृत्य कर रही है। जनता पार्टी के झूठ को बहुत करीब से देख रही हैं। अहम उसका झूठ फिर से बेनकाब हुआ है।' 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया था कि निर्वाचन आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और निवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्तियाँ दर्ज कीं। खबर के अनुसार, इन आपत्तियों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने और प्रक्रियागत बदलावों को लेकर सवाल उठाए गए थे। दोनों आयुक्तों ने आयोग के कुछ कदमों को "अनधिकृत" और "अवैध" भी बताया था।

नयी दिल्ली २७/०९
(संवाददाता): कांग्रेस ने
रविवार को मोदी सरकार पर
“दलित विरोधी” और
“आदिवासी विरोधी” होने का
आरोप लगाया और कहा कि
पार्टी उज्जरखंड में पिछले महिने
पार्टी अध्यक्ष मणिकार्जुन खरगे
की रैली के बाद किए गए
“शुद्धीकरण” कार्यक्रम को
लेकर २९ सितंबर को दलित-
आदिवासी स्वाभिमान बैठक
आयोजित करेगी। यह बैठक
कांग्रेस अनुसूचित जाति
(एससी)/अनुसूचित जनजाति
(एसटी) सांसद मंच की ओर
से अखिल भारतीय कांग्रेस
कमेटी (एआईसीसी) के
अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति विभागों के सहयोग
से कांस्टिट्यूशन जलब ऑफ

इंडिया के मावलकर हॉल में आयोजित की जाएगी। कांग्रेस सांसद महू रवि ने कहा, “बैठक में आगस्त में उज्जराखंड के हल्द्वानी में खरगे जी की जनसभा के बाद हुए शुद्धीकरण कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी।” उन्होंने कहा कि पूरे देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उल्लंघन हुआ है। रवि ने कहा कि बैठक भविष्य में एससी घटनाओं को रोकने के लिए एससी रूपरेखा तैयार करेगी। उन्होंने कहा बताया कि बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी कांग्रेस

दरमध्य, पूर्व सांसद, कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री, विधायक और एआईसीसी के प्रतिनिधियों शामिल होंगे। रवि ने कहा कि यह बैठक मुख्य रूप से हलद्वानी में खरोठी की जनसभा के बाद किए गए शुद्धीकरण कार्यक्रम पर चर्चा के लिए बुलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, “यह कहने वाला खरोठी जी का अपमान नहीं था, बल्कि पूरे एससी/एसटी समाज का अपमान था।” रवि ने कहा कि उज्जराखंड सरकार ने शुरुआत में प्राथमिकी दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि सांसदों के संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन करने के बाद हलद्वानी में प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने आरोप लगाया, “भाजपा शासित राज्य में यही हो रहा है।” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस

घटना का समर्थन कर रही है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कथित तौर पर “शुद्धीकरण” कार्यक्रम करने वाले राम सेना के सदस्यों का खुलकर समर्थन किया।

रवि ने दावा किया कि भाजपा जानबूझकर जाति के आधार पर लोगों के बीच विभाजन पैदा करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं मनोज कुमार, तनुज पुनिया, कर्मवीर बौद्ध, भजन लाल जाटव और विक्रांत भूरिया के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रवि ने कहा, “प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी), गृहमंत्री (अमित शाह) और उज्जराखंड के मुख्यमंत्री (पुष्कर सिंह धामी) ने अब तक इस घटना की निंदा नहीं की है।”

चुनाव आयाग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का कांग्रेस को हक नहीं-सीएम सम्राट चौधरी

पटना २७/०९
(संवाददाता): बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जाम मुज्य चुनाव आयुक्तों ने जिन कृषि और निष्पविबुज हुए उन्हें मलाईदा पद दिए गए थे, इसलिए पार्टी को निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। यहां एक संवाददाता सज्मेलन को संबोधित करते हुए, भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि विपक्ष एसआईआर को लेकर झूठ शोर मचा रहा है और दावा किया कि देश की सभी समस्याओं, चाहे वे आर्थिक हों या कोई और के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि उसने दशकों तक देश पर शासन किया है। चौधरी ने बताया, कांग्रेस के शासनकाल में ही पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एम.एस. गिल केंद्रीय मंत्री बने थे आक और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी.एन. शेणन ने कांग्रेस के टिकट



पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बिहार में सरकार की अगुवाई करने वाले पार्टी के पहले नेता, चौधरी ने कहा, वीएस रमादेवी का भी मामला था, जो काफ़ी समय पहले चुनाव आयुक्त थीं और बाद में उन्हें राज्यपाल बनाया गया था। इसलिए, कांग्रेस को निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। चौधरी की ये बातें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के नए हमलों के बीच सामने आई हैं; विपक्ष उन पर केंद्र में सज़ाधारी भाजपा का पक्ष लेने का आरोप लगता रहा है। ये हमले 'द इंडियन एक्सप्रेस'।

की एक खबर के बाद हुए, जिसमें बताया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई थी इनका कहना था कि ये फैसले और आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे। चौधरी और आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सदस्यों इस व्यापक कव्याद को लेकर झूठा शोर मचा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कांग्रेस का युवराज बताते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्होंने पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले बिहार का दौरा किया था और आरोप लगाया था कि कई मतदाताओं के नाम गैर-कानूनी तरीके से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।

साबरमती २७/०९
(संवाददाता): केंद्रीय गृह एवं
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने
रविवार को गुजरात के
साबरमती रेलवे स्टेशन से देश
की पहली एलएनजी से चलने
वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
इस दौरान साबरमती डिवीजन
की कई रेलवे परियोजनाओं का
उद्घाटन, शिलान्यास और
शुभारंभ भी किया गया। इन
परियोजनाओं की कुल लागत
1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा
है। इन परियोजनाओं में
डज्यूएजी-12 लोकोमोटिव
रखरखाव शोड, स्वचालित
सिग्नलिंग प्रणाली, कवच सुरक्षा
प्रणाली और साबरमती-सरखेज
रेल लाइन का दोहरीकरण
शामिल है। अमित शाह ने इस
दौरान रेलवे के बुनियादी ढांचे,
सुरक्षा और नई तकनीक के
इस्तेमाल पर भी बात की। अमित
शाह ने कहा कि दिल्ली से यात्रा
करते समय वह कई बार
साबरमती रेलवे स्टेशन पर उतर



चुके हैं। लंबे समय बाद साबरमती स्टेशन में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने रेलवे के अधिकारियों और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, साबरमती रेलवे डिवीजन से लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पूरी टीम को मेरी हार्दिक बधाई। इतने लंबे समय बाद साबरमती स्टेशन को इस रूप में देखना बेहद खास है। अमित शाह ने बताया कि करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से साबरमती में डज़र्यूपूजी-12 लोकोमोटिव रखरखाव शेड तैयार किया गया है। यह शेड 300 डज़र्यूपूजी-12 उच्च क्षमता वाले



चुके हैं। लंबे समय बाद साबरमती स्टेशन में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने रेलवे के अधिकारियों और पूरी टीम को बधाई दी उन्होंने कहा, साबरमती रेलवे डिवीजन से लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पूरी टीम को मेरी हार्दिक बधाई। इनने लंबे समय बाद साबरमती स्टेशन को इस रूप में देखा बेहद खास है। अमित शाह ने बताया कि करीब 700 करोड़ रुपये की लागत से साबरमती में डरज्यूएजी-12 लोकोमोटिव खरखवा शेड तैयार किया गया है। यह शेड 300 डरज्यूएजी-12 उच्च क्षमता वाले

बिजली से चलने वाले रेल इंजनों के रखरखाव के लिए बनाया गया है। डल्ह्यूएजी-12 इंजन करीब 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता वाला है और भारी तथा लंबी मालगाड़ियों को चलाने के लिए बनाया गया है। अमित शाह ने इसे रेलवे के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अमित शाह ने कहा कि डल्ह्यूएजी-12 इंजन भारी मात्रा में माल ढोने में सक्षम है। उनके अनुसार, एक डल्ह्यूएजी-12 लोकोमोटिव करीब 600 टर्कों के बराबर माल ढोने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि पहले

माल ढुलाई के लिए दो लोकोमोटिव लगाने पड़ते थे, लेकिन अब एक डब्ल्यूएजी-12 लोकोमोटिव यह काम कर सकता है। साबरमती से जुड़े रेलखंडों पर कवच और स्वचालित सिग्नलिंग से जुड़े काम भी परियोजनाओं का हिस्सा हैं।

अहमदाबाद-पालनपुर और अहमदाबाद-समाखियाली रेलखंड पर करीब 404 किलोमीटर के हिस्से में कवच प्रणाली लागती योजना है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 411 करोड़ रुपये है वहीं, साबरमती-कलोल-भाड़व मोटीदाऊ और साबरमती-साणंद-जखवाड़ा रेलखंड पर 122.57 किलोमीटर में स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू की गई है। इसकी लागत करीब 118.83 करोड़ रुपये बताई गई है। यह प्रणाली ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने और रेल मार्ग की क्षमता

बढ़ाने में मदद करती है। अमित शाह ने साबरमती-सरखेज रेल लाइन के दोहरीकरण का भी जिक्र किया। करीब 313.27 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 21 किलोमीटर लंबे रेलखंड से जुड़ी है और इसे मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना में साबरमती, गांधीग्राम, वस्त्रापुर और सरखेज स्टेशनों से जुड़े काम के साथ पुलों और सड़क के नीचे से गुजरने वाले रास्तों से जुड़े काम भी शामिल हैं। अमित शाह ने देश की पहली एलएनजी आधारित ट्रेन को भी डीज़ल दिखाई। इस ट्रेन में डीजल और एलएनजी, दोनों में चलने वाली प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। साबरमती इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो की दो 1,400 हॉर्स पावर वाली ड्राइविंग पावर कारों में यह प्रणाली लगाई गई है। इसमें एलएनजी करीब 40 प्रतिशत तक डीजल की जगह ले सकती है।

ग्लोबल मिशन पर निकलेंगे पीएम मोदी, दिसंबर में यूएस, कनाडा, यूरोप यात्रा से नया इतिहास रचने की तैयारी

नयी दिल्ली २६/०९ (संवाददाता): भारत की कूटनीतिक गतिविधियां दिसंबर महीने में एक बड़े रणनीतिक अभियान का रूप लेने जा रही हैं और अब पूरी दुनिया मोदी की कूटनीति का कमाल देखने वाली है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित बहु-देशीय यात्रा में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कम से कम दो देशों को शामिल किए जाने की तैयारी की खबर है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी यात्रा कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत दिसंबर को केवल राजनयिक यात्राओं का महीना नहीं, बल्कि व्यापारिक समझौतों, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शक्ति-संतुलन को साधने के अवसर के रूप में देख रहा है। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी मोदी को इस कूटनीतिक अभियान का सबसे बड़ा पड़ाव अमेरिका हो सकता है।

ओडिशा में गहरे दबाव के चलते कुदरत का कहर! भारी बारिश, भूस्खलन और उफान पर नदियां

भुवनेश्वर २६/०९ (संवाददाता): ओडिशा में एक बार फिर कुदरत का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले गहरे दबाव के कारण शुक्रवार को ओडिशा के कई हिस्सों में प्रलयंकारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन के अनुसार, राज्य भर में कम से कम 63 स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक की मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। इस भीषण वर्षा के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है और शहरों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित जिलों में स्कूलों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। तटीय राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में निचले इलाकों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के करीब 14,5०0 लोगों को 2,061 राहत केंद्रों में स्थानांतरित किया गया है। एक दिन पहले आंध्र प्रदेश के तट से टकराया गहरे दबाव का क्षेत्र ओडिशा में प्रवेश कर गया जिसके कारण शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बहुत



भारी बारिश हुई। नबरंगपुर जिले का तेंतुलीखुंटी 395 मिलीमीटर बारिश के साथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। इसके बाद नंदाहांडी में 344 मिलीमीटर और कोरापुट जिले के बोरीगुमा में 307.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। एक अधिकारी ने बताया कि इस आपदा से दक्षिणी ओडिशा के छह जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और भुवनेश्वर समेत पश्चिमी तथा तटीय क्षेत्रों में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि बालासोर जिले में जलाका और बुढ़ाबलंगा नदियों तथा जाजपुर जिले में बैतरणी और कानी नदियों का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे एक बार फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मानसून के मौसम की शुरुआत से ही राज्य में पहले ही दो बार

है जिसका सीधा और ठोस फायदा भारतीय उद्योग और निर्यातकों को मिले। यहीं से भारत की कूटनीति का दूसरा और अधिक कठिन पक्ष सामने आता है। अमेरिका ने रूस और ईरान से जुड़े नए प्रतिबंध कानून के जरिए रूस की ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाने की संभावना का रास्ता खोला है। इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा रणनीति पर पड़ सकता है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ बातचीत में भारत की आर्थिक और रणनीतिक चिंताओं को रखा। अमेरिका की ओर से भी यह संकेत दिया गया कि ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर साझेदार देशों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। यहां भारत की नीति को समझना जरूरी है। नई दिल्ली न तो रूस से संबंध तोड़ रही है और न ही अमेरिका से दूरी बना रही है। सितंबर में मोदी



और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। मोदी ने रूस के सामने भी युद्ध को समाप्त करने और संवाद व कूटनीति के रास्ते आगे बढ़ने की बात रखी। इसी दौरान भारत के विदेश मंत्री की यूक्रेन यात्रा ने यह संदेश दिया कि भारत केवल एक पक्ष से बात करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि अलग-अलग शक्ति केंद्रों से संवाद बनाए रखने वाला देश है। यही इस वर्ष की भारतीय कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यूक्रेन युद्ध जारी है, पश्चिम एशिया में संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति पर संकट की

आशंका बनी हुई है, अमेरिका-रूस तनाव गहरा रहा है और चीन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे वातावरण में भारत ने रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ व्यापार तथा रणनीतिक सहयोग बढ़ाया, यूरोप के साथ आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी मजबूत की और यूक्रेन के साथ शांति संबंधी संवाद जारी रखा। उधर, यूरोप के मोर्चे पर भारत को बड़ी उपलब्धि मिल चुकी है। भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पूरी की। सितंबर में यूरोपीय आयोग ने

सोनम वांगचुक ने लदाख की तुलना चीन के कब्जे वाले तिब्बत से करके खड़ा किया विवाद

नयी दिल्ली २६/०९ (संवाददाता): लदाख में अधिकारों, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर लंबे समय से मुखर रहे जलवायु कार्यकर्ता और लेह एपेर्जस बांडी के सदस्य सोनम वांगचुक अब अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। लदाख की मौजूदा परिस्थितियों की तुलना चीन के कब्जे वाले तिब्बत से करने पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कड़ी आपर्जि जताई है। धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने वांगचुक की टिप्पणी को न केवल अनुचित, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाली बताया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के आधिकारिक प्रवक्ता तेनजिन लेज्शे ने शुक्रवार शाम कहा कि प्रशासन वांगचुक के हालिया सार्वजनिक बयान को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। उन्होंने कहा कि लदाख की स्थिति की तुलना तिब्बत के भीतर की परिस्थितियों से करना गलत और वास्तविकता से परे है। उनके मुताबिक तिब्बत आज भी चीन के सजावादी शासन के अधीन है, जहां तिब्बतियों के मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर व्यवस्थित



दमन जारी है तथा उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा की पहली बरसी पर लोगों को संबोधित करते हुए वांगचुक ने लदाख में पिछले वर्ष हुए घटनाक्रम को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने के कथित आश्वासनों को पूरा नहीं किया जाना ही पिछले वर्ष के आंदोलन की मूल वजह था।

वांगचुक ने दावा किया कि पिछले साल प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में चार लोगों की मौत हुई और करीब 90 लोग घायल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे निहत्थे युवाओं पर स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाई गईं। उनका कहना था

कि मृतकों के सोने, पीठ और सिर में गोलियां लगी थीं और यह महज भीड़ को नियंत्रित करने के लिए छोड़े गए छर्रे नहीं थे। इसी संदर्भ में वांगचुक ने लदाख की तुलना तिब्बत से करते हुए कहा कि लदाख में कथित तौर पर ऐसी ज्यादतियां हो रही हैं, जो उनके अनुसार चीन भी तिब्बत में नहीं कर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि लदाख के लोगों ने भारत को इसलिए चुना था क्योंकि यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हालांकि, इसी तुलना ने अब तिब्बती प्रशासन को खुलकर सामने आने के लिए मजबूर कर दिया है। वांगचुक ने पिछले वर्ष हुई मौतों की जांच के लिए जनता की अदालत गठित करने की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई

है। उन्होंने दावा किया कि 24 सितंबर 2025 को मारे गए चार प्रदर्शनकारी अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे और उन पर कथित रूप से अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया गया। वांगचुक ने आंदोलन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि 2020 में लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव से पहले लदाख के कुछ प्रतिनिधियों को विशेष विमान से नई दिल्ली ले जाया गया था और उन्हें राज्य का दर्जा तथा छठी अनुसूची का दर्जा देने का आश्वासन दिया गया था। उनके मुताबिक इन कथित आश्वासनों को पूरा नहीं किए जाने से लोगों में असंतोष बढ़ा और अंततः पिछले साल प्रदर्शन भड़क उठे। हम आपको याद दिला दें कि हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई गई थीं। आगजनी और दंगे के आरोपों के बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें वांगचुक भी शामिल थे। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें जोधपुर जेल भेजा गया। करीब 170 दिन हिरासत में रहने के बाद केंद्र सरकार ने इस वर्ष

14 मार्च को उनकी हिरासत वापस ले ली, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। अब वांगचुक ने आशंका जताई है कि लदाख में कथित अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें किसी मुठभेड़ में निशाना बनाया जा सकता है। दूसरी ओर, तिब्बती प्रशासन की आपर्जि ने इस पूरे विवाद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। देखा जाये तो एक तरफ वांगचुक लदाख में लोकतांत्रिक अधिकारों और कथित सरकारी वादाखिलाफी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यह स्पष्ट कर रहा है कि चीन के अश्वीन तिब्बत की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को लदाख से जोड़ना उचित नहीं है। बहरहाल, इस विवाद ने लदाख के अधिकारों की लड़ाई को अब केवल राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग तक सीमित नहीं रहने दिया है। सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है कि लोकतांत्रिक भारत में शासन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर उठाए जा रहे सवालों की तुलना चीन के तिब्बत शासन से किस सीमा तक की जा सकती है और इस तुलना की राजनीतिक तथा ऐतिहासिक कीमत क्या होगी।

केरल में वंदे मातरम् न गाने पर भाजपा का आरोप

तिरुवनंतपुरम २६/०९ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने रविवार को आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के आधिकारिक समारोहों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' नहीं गाने का फैसला यूडीएफ सरकार ने "जानबूझकर" लिया था और चेतानवी दी कि इसके "राजनीतिक और कानूनी परिणाम" होंगे। उन्होंने कहा, "हम इसे यू ही नहीं छोड़ सकते।" चंद्रशेखर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना तथा गैर-भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश में वंदे मातरम् गाया गया, लेकिन केरल में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला

मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन के नेतृत्व वाली सरकार पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और जमात-ए-इस्लामी के "निर्यंत्रण" के कारण लिया गया उन्होंने एक दिन पहले नयी दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की ओर से आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम् का पूरा संस्करण गाए जाने का कथित रूप से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा विरोध किए जाने की भी आलोचना की। नेमोम से भाजपा विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि वहां जो हुआ, उसे बर्बाद करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "जब इस देश द्वारा स्वीकार की गई एक महिला वंदे मातरम् का गायन रोकने की कोशिश करती है।

नयी दिल्ली २६/०९ (संवाददाता): विरोधी दलों के गठबंधन INDIA ज्लॉक की 30 सितंबर को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन ज़लब में एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के %स्पेशल इंटेसिव रिविजन% (स्ट्रुक्) प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ नए कदम उठाने जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी के शामिल होने की पूरी उम्मीद है। यह प्रस्तावित बैठक ऐसे समय में

हो रही है जब स्ट्रुक् प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को लेकर चुनाव आयोग के अंदर मतभेदों की खबरें सामने आई हैं और विपक्षी पार्टियों के बीच आयोग को लेकर तालमेल बढ़ा है। सूत्रों ने बताया कि पार्टियां इस मुद्दे पर एक-दूसरे के संपर्क में हैं और मिलकर जवाब देने पर चर्चा कर रही हैं। CPI(M), CPI, CPI(ML)-लिबरेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIA प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है। कांग्रेस ने भी कुमार की आलोचना तेज कर दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 29 सितंबर को होनी है, जो INDIA ज्लॉक की प्रस्तावित बैठक से एक दिन पहले होगी। इसमें इस मुद्दे पर पार्टी के रुख

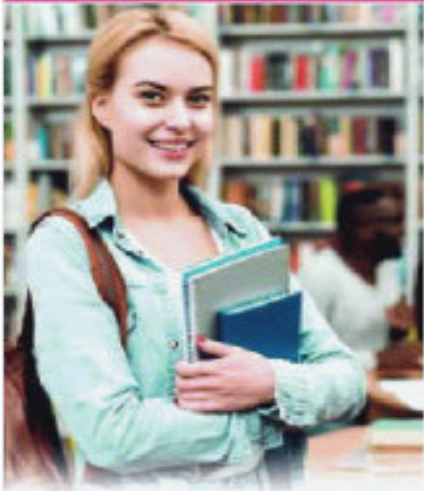


पर चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग के मुद्दे ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच भी सहमति का एक अनोखा माहौल बनाया है; ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC और CPI(M) अब इस मामले पर मिलकर काम कर रही हैं। CPI(M) के महासचिव एम.ए. बेबी ने दृढ़दृष्ट ज्लॉक और अन्य विपक्षी नेताओं को

पत्र लिखकर ताजा घटनाक्रम पर चर्चा के लिए बैठक की मांग की। बाद में उन्होंने बनर्जी से बात की, जिन्होंने सहमति जताई कि स्थिति को देखते हुए मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। विपक्षी पार्टियां कुमार को हटाने की मांग करते हुए एक नया नोटिस भी तैयार कर रही हैं। कानूनी विशेषज्ञों की जांच के बाद इस प्रस्तावित नोटिस

को संसद के दोनों सदनों के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है।

अगर इसे पेश किया जाता है, तो यह दृष्टष्ट के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई शुरू करने की विपक्ष की तीसरी कोशिश होगी। विपक्ष की यह नई लामबंदी %द इंडियन एक्स्प्रेस% की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुई है, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने स्ट्रुक् प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कई बार आपर्जि जताई थी। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि अलग-अलग राय और टिप्पणियां संस्थागत चर्चाओं का सामान्य हिस्सा हैं।



ऑनलाइन बिजनेस को सफल बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत आसान है। वहीं ऑनलाइन बिजनेस को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सही प्लानिंग और स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। वहीं सबसेसं पाने के लिए आप सही बिजनेस आइडिया चुनने से लेकर सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल तक की जरूरत होती है। डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ चिट-चैट के लिए नहीं बल्कि अन्य तमाम कामों के लिए भी हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए लोग ऑनलाइन बिजनेस का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि इसमें निवेश और जोखिम अधिक नहीं होता है। अगर आप भी घर बैठे अपनी रिकल्स और क्रेडिटिविटी का इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं।

फील्ड रिसर्च

किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको मार्केट की रिसर्च जरूर करना चाहिए। ऐसे इसलिए जरूरी होता है, जिससे आपको मार्केट की डिमांड और उसमें किस तरह से प्रोडक्ट फिट होगा, इस बारे में जानकारी मिलती है।

बिजनेस प्लान

बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग करना जरूरी होता है। इससे आपको अपनी कबिलियत के साथ-साथ प्रोफिट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और टारगेट ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करें।

बिजनेस रजिस्टर करें

बिजनेस की प्लानिंग के बाद आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसके लिए सबसे पहले बिजनेस स्ट्रकर बनाएं और जरूरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करें।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर अपना डालने के साथ ही आप खुद का भी ऑनलाइन पेज क्रिएट करें। आप यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के साथ शॉपिफाई और वडप्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

डिजिटल मार्केटिंग

जब तक आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। क्योंकि आज का समय टेक्नोलॉजी का है, इसलिए मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। इसलिए आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए फेसबुक, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर्स के कैपेन की भी सहायता ले सकते हैं।



एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2028 तक भारत का हेल्थकेयर सेक्टर करीब 280 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल लगभग 40 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। उम्मीद है कि सन् 2028 तक इस सेक्टर का वर्कफोर्स करीब 74 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। हेल्थकेयर में एफडीआई के आने से मेडिकल टूरिज्म जैसे नए सेक्टर्स उभरकर सामने आए हैं। टेलीमेडिसिन का बाजार भी तेजी से विकसित हो रहा है।



लैब टेक्निशियन

अगर आपने केमिस्ट्री में बीएससी/एमएससी या फिर लैब टेक्निशियन से संबंधित कोई डिप्लोमा किया है, तो आपके लिए स्कॉप की कमी नहीं है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट प्रभात सेमवाल कहते हैं कि किसी भी शोध संस्थान, प्राइवेट या सरकारी लैब, फार्मा कंपनी के फार्मा केमिस्ट्री/बायोकेमिस्ट्री विंग में असिस्टेंट, टेक्निशियन, इंवांज, लैब इंस्ट्रक्टर या मैनेजर के तौर पर अच्छा पैकेज और शोध पा सकते हैं। हां, इस फील्ड में काम करने के लिए इसमें रुचि होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह टेक्निकल वर्क है।

कई कोर्स, कई रास्ते

मेडिकल फील्ड में प्रवेश के लिए एमबीबीएस के अलावा बीडीएस (डेंटल), बीएचएमएस (होम्योपैथी), बीएएमएस (आयुर्वेद) जैसे परंपरागत डिग्री कोर्स हैं। इनके अलावा, विद्यार्थी 12वीं के बाद पैरामेडिकल के तहत विभिन्न कोर्स कर सकते हैं, जो डिग्री से लेकर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और शॉर्टटर्म कोर्सेज के रूप में ऑफर किए जाते हैं। देश के सरकारी और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑल इंडिया या स्टेट लेवल पर होने वाले मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। वहीं एम्स, एचएमसी आदि अलग से प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी अपनी प्रवेश परीक्षा लेते हैं।



नए अवसर सृजित कर रहे हैं ऑनलाइन हेल्थकेयर स्टार्ट-अप्स

ऑनलाइन हेल्थकेयर स्टार्ट-अप्स में नए अवसर सृजित हो रहे हैं। तकनीकी विकास के कारण टेक्निकली स्किलड प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के अलावा पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, लैब टेक्निशियंस आदि को हाथों-हाथ लिया जा रहा है। इसी तरह ज्योग्नेस्टिक्स और पैथोलॉजिकल लैब्स की संख्या बढ़ने से प्रशिक्षित टेक्निशियंस की काफी मांग देखी जा रही है। मेडिकल फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स के जरिए जानते हैं इस फील्ड में विभिन्न करियर ऑप्शंस के बारे में।

होम्योपैथी

डॉ. नीतू कहती हैं कि भारत में करियर के लिहाज से होम्योपैथी वैश्व स्तर पर पहली चॉइस नहीं बनती लेकिन इस पद्धति में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। बात चाहे सरकारी क्षेत्र में जॉब की हो या प्राइवेट प्रैक्टिस की, अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई की है और नए घटनाक्रम से अपडेटेड रहते हैं, तो पहचान बनाने में देर नहीं लगती।

वैटरनरी साइंस

डॉ. तीस्ता वाइल्डलाइफ एसोएफ्स के साथ जुड़ी हैं। वे कहती हैं कि वैटरनरी साइंस के क्षेत्र में काफी फील्ड वर्क होता है। इसलिए जो विद्यार्थी इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें टेक्निकली साउंड होने के अलावा मानसिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के अलावा एनजीओ, वन्यजीवों के लिए काम करने वाली संस्थाओं और प्राइवेट सेक्टर में वैटरनरी डॉक्टर्स की अच्छी मांग है। मगर कहीं भी नौकरी करने से पहले ट्रायल बेसिस पर वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना बेहतर रहता है। विदेशों में वैटरनरी डॉक्टर्स को रिसर्च से लेकर तमाम तरह के आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है।

फिजियोथैरेपी

आजकल अवसर लोग पीटदर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, स्पोन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क आदि की शिकायत करते हैं। खिलाड़ियों को भी गांठ-बगांठ बोट लगती रहती है। ऐसे में फिजियोथैरेपिस्ट की मांग दिनों-दिन

बढ़ रही है। फिजियोथैरेपिस्ट प्रियंका तिवारी बताती हैं कि विद्यार्थी 12वीं के बाद बीपीटी या डिप्लोमा जैसा कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ढेर सारे अवसर हैं।

फार्मेसी

एक निजी अस्पताल में फार्मेसी के हैड अमित गुप्ता के अनुसार, फार्मेसी फील्ड में युवाओं के लिए बहुत अवसर है। विज्ञान से 12वीं पास युवा बी फार्मा, एम फार्मा या डिप्लोमा करके फार्मा सेक्टर, हॉस्पिटल्स, रिटेल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एमआर या मटेरियल मैनेजर जैसे पदों पर जॉब हासिल कर सकते हैं।



ऑक्यूपेशनल थैरेपी

मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है। अब सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, डाउन्स सिंड्रोम जैसी जेनेटिक बीमारियों के शिकार लोगों के लिए भी विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिन्हें ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट कहते हैं। ऐसे ही ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट कपिल कुमार कहते हैं कि इस बीमारी की वजह से शरीर का कोई भी हिस्सा जब काम करना बंद कर देता है, तो इस थैरेपी की मदद से उसे सामान्य बनाया जाता है। आज जो भी युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं, वे यह सोचकर आए कि आने वाले वक्त में उन्हें किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना है।



आयुर्वेद

आयुर्वेद में एक बीमारी के लिए सैकड़ों औषधियां हैं। एमबीबीएस की तरह आयुर्वेद का कोर्स भी साढ़े पांच साल का होता है, जिसमें साढ़े चार साल एकेडमिक्स और एक साल की इंटर्नशिप होती है। प्रोफेशनल्स के सामने सरकारी, प्राइवेट नौकरी से लेकर अपनी निजी प्रैक्टिस करने का विकल्प खुला होता है। वे कहते हैं कि सरकार अगर आयुर्वेद को वैकल्पिक चिकित्सा के तहत प्रोत्साहन, ग्रेजुएट्स को वाजिब स्टाइपेंड दे, तो अच्छे टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

ब्रिज मेंटरशिप से मिलेगी सफलता की नई राह

आज के युग में प्रतिस्पर्धा बल रही है, फिर चाहे आप स्टूडेंट हों या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हों। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में सभी को किसी न किसी मेंटर की जरूरत होती है। मेंटरशिप में एक से अधिक एक्सपीरियंस व्यक्ति किसी अन्य पेशेवर के साथ बुद्धिमत्ता और ज्ञान साझा करते हैं। जिससे कि उनको आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। अधिक एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को मेंटर कहा जाता है। आमतौर पर मेंटर अपने करियर या शिक्षा में आगे होते हैं। ऐसे में वह नए लोगों को अपने अनुभव के आधार पर मोटिवेट कर उनका मोटिवेट करते हैं और रोल मॉडल के रूप में अपना काम कर सकते हैं।

ब्रिज मेंटरशिप

एक रिसर्च से पता चलता है कि 71% मेंटर अपने ही पेशे वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना पसंद करते हैं। इस अवधारणा को ब्रिज मेंटरशिप कहा जाता है। जहां पर मेंटर और मीडि नियमित रूप से आगने-सामने मिलते हैं। जिससे कि दोनों तरफ से साझेदारी बनाई जा सके। इस प्रोसेस के दौरान मेंटी को मेंटर के दृष्टिकोण, अनुभूति अनुभवों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की गंभीर समझ हासिल करने में सहायता मिलती है। यह प्रक्रिया प्रशिक्षण के साथ सहानुभूति और अंतर-सांस्कृतिक संचार को बढ़ावा देती है।

खुली बातचीत को करें प्रोत्साहित

अधिकतर मेंटरशिप की तरह ही ब्रिज मेंटरशिप के अपने कुछ दिशा-निर्देश होते हैं। जिनमें मेंटी और मेंटर दोनों की तरफ से विश्वास और गोपनीयता शामिल है। इस आधार पर एक सहायक और सेफ वातावरण बनता है। जिससे दोनों तरफ से खुली बातचीत को प्रोत्साहन मिलता है। यह प्रोसेस दोनों पक्ष के स्तर पर विजय पाने में सहायता करती है। वहीं सभी लोगों के लिए एक सांस्कृतिक रूप से समक्ष कार्य का वातावरण का निर्माण करती है।

कार्यक्रमों में लें हिस्सा

आप अपने क्षेत्र या अपने विशिष्ट समुदायों के भीतर संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रिज मेंटरशिप के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। इससे आपको उन लीडर्स तक पहुंचने में सहायता मिलेगी, जोकि उच्च पदों पर कार्यरत हैं। साथ ही आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी भलीभांति परिचित हैं।

खोजें ऐसे सेंटर

बता दें कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म खोज सकते हैं, जो मेंटर से मिलाने पर फोकस करते

हैं। वहीं आप अपने संगठन के अंदर एक ऐसी परियोजना में हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें तमाम विभागों या फिर कार्यात्मक क्षेत्रों के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा दूसरे विभागों के लीडर्स से भी मिल सकते हैं। ब्रिज मेंटरशिप के लिए आपको सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलना होता है। जहां पर आप संभावित सेंटर्स से मिलने के लिए कह सकते हैं, जिससे कि आप उनके विचारों को जान सकें। साथ ही यह भी कि क्या वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं।



कलिंग समाचार



संपादकीय

जेन अल्फा ने उठानी शुरु की हक की आवाज

देश में जेन जी के बाद अब जेन अल्फा का विरोध–प्रदर्शन और अपने हक के लिए आवाज उठाने का सिलसिला शुरु हो चुका है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां खस्ताहाल सरकारी स्कूलों या बुनियादी सुविधाओं की कमी पर बच्चों ने सामने आकर विरोध करना शुरु कर दिया है। गौरतलब है कि 2010 या उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे जनरेशन अल्फा का हिस्सा हैं। ये बच्चे पूरी तरह से इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधुनिक दौर में जन्मे हैं, लिहाजा तकनीकी तौर पर अपनी पिछली पीढ़ियों के मुकाबले ये कहीं ज्यादा सक्षम हैं।भारत में इस पीढ़ी के बच्चों की अनुमानित संं या 32.7 करोड़ से लेकर 41.7 करोड़ के बीच है। इसका मतलब यह है कि भारत की पूरी आबादी का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा केवल इसी उम्र वर्ग का है। आंकड़े बताते हैं कि 0 से 17 साल की उम्र वाले इन बच्चों की बढ़ौलत भारत लंबे समय तक सबसे युवा आबादी वाला देश बना रहेगा। लेकिन हम खुशहाल, स्वस्थ, शिक्षित युवा देश बनने का गौरव हासिल करेंगे या संघर्षों वाला देश बन कर रह जाएंगे, यह आज का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक माहौल ही तय करेगा। फिलहाल जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं, उनसे जाहिर है कि बच्चों की शिक्षा, पोषण, उनके सर्वांगीण विकास के पैमानों पर सरकार पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। भारत शिक्षा पर अपनी अर्थव्यवस्था का 4.1प्रतिशत खर्च करता है। यह यूनेस्को के तय न्यूनतम 4प्रतिशत मानक से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन सरकार के कुल खर्च में शिक्षा की हिस्सेदारी घटकर 14.2प्रतिशत रह गई है। यूनेस्को के मुताबिक यह हिस्सा कम से कम 15प्रतिशत होना चाहिए। 2015 में सरकार के कुल खर्च का 15.7प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता था। लेकिन 11 साल बाद भी यह खर्च बढ़ा नहीं बल्कि कम ही हुआ है, तो यह दिखाता है कि सरकार शिक्षा को लेकर कितनी लापरवाह है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बीते दिनों स्कूली बच्चों ने खराब और दलदल वाली कच्ची सड़क को पक्का करवाने की मांग को लेकर हाथों में तिरंगा लेकर लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल मार्च किया और जिलाधीश कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद प्रशासन को झुकना पड़ा। इसी तरह मध्यप्रदेश के विदिशा में बस किराया बढ़ने पर छात्राओं ने विधायक मुकेश टंडन से जवाब मांगा कि हर दिन 25 रुपए का किराया कैसे दें। छात्राओं ने कहा कि हमारी बड़ी बहनें जो पढ़ने के लिए विदिशा से रायसेन- भोपाल और कई जगहों पर जाती हैं, उन्हें बहुत अधिक किराया देना पड़ता है। हम पहले जो किराया पांच रुपए देते थे वो 25 रुपए हो गया है। ध्यान रहे कि हाल ही में विदिशा के ही ककरौआ गांव का मामला सामने आया, जहां बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए हर रोज बेतवा नदी पर बने चेक-डैम के करीब 10 कांक्रीट के खंभों को कूदकर पार करते थे और फिर हाईस्कूल जा पाते थे। इस खतरनाक रास्ते के पार करने का वीडियो सामने आया, खबर छपी तो प्रशासन ने तुरंत सज़ान लिया और महज एक दिन के भीतर गांव के स्कूल को अपग्रेड कर हाई स्कूल का दर्जा दे दिया। डेमोग्राफ़िक्स इस मामले से यह भी जाहिर होता है कि जनहित के लिए लिखी और बनाई गई खबरें आज भी सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती हैं। हालांकि अब मीडिया की प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर काफी हद तक सच्चाई सामने आ जाती है। विदिशा जैसा ही मामला उत्तराखंड के चौबट्टाखाल से सामने आया, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि साल भर पहले बारिश में बह गया पुल आज तक नहीं बना। गांव वालों की मांग पर भाजपा सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। खस्ताहाल स्कूलों से बच्चों की ज़िंदगी पर संकट मंडराने की घटनाएं भी सामने आई हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बबलाद गांव में जिला परिषद स्कूल में छत का स्लैब गिरने से 13 छात्र घायल हो गए। इस घटना ने पिछले साल राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में हुए हादसे की याद दिलाई, जहां सरकारी स्कूल की जर्जर छत गिरने से सात मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। हाल ही में उप्र के पीलीभीत के अमृता खास गांव में श्रीबालक राम सरस्वती शिशु मंदिर में क्लास के ऊपर लगी भारी-भरकम टीन की छत भरभरा कर नीचे आ गिरी, जिसमें बारह बच्चे और 2 शिक्षिकाएं दब गईं।

आंदोलनों की शक्ति–स्वतंत्रता संग्राम से जेन जी तक

अरुण कुमार डनायक
यूनियन और श्रमिक आंदोलन पूर्ववर्ती आंदोलनों की तरह यह छात्र आंदोलन भी कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण और गांधीवादी सत्याग्रह की तरह अहिंसक रहा तथा व्यवस्था की कमियों को सुधारने के लिए आगे आया।

वर्तमान निराशाजनक राजनीतिक माहौल में जेन जी के इन निडर युवाओं ने बदलाव की उ मीद जगाई है। भारत का स्वतंत्रता दिवस अन्याय के विरुद्ध लोकतांत्रिक और अहिंसक संघर्ष की निरंतर जि मेदारी का प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता में अनेक धाराओं का योगदान रहा, पर गांधी के अहिंसक आंदोलनों ने जनसामान्य की ललक को व्यापक जनआंदोलन में बदल दिया। गांधी के नेतृत्व में असहयोग, दांडी मार्च, सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जनसहयोग से सफल रहे। भारत छोड़ो आंदोलन ने शीर्ष नेतृत्व की गिर तारी के बावजूद स्वतंत्रता की निर्णायक चेतना जगाई और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी।

विदेश में अब तो अग्निनत इंडियन रेस्तरां खुल गए हैं। इनके नाम हिन्दी या उर्दू में होते हैं। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों की जड़ें भक्ति आंदोलन में हैं, जब कबीर, नानक और रेदास ने सामाजिक रूढ़ियों व भेदभाव के विरुद्ध जनचेतना जगाई। किन्तु आज़ादी के पहले हुए आंदोलनों ने भी जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष को दिशा दी। 1927 के महाड सत्याग्रह में डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने चवदार तालाब से पानी पीकर सार्वजनिक जलस्रोतों पर अधिकार जताया। महात्मा गांधी की हरिजन यात्रा ने अस्पृश्यता के विरुद्ध जनमत और मंदिर प्रवेश व शिक्षा के अधिकारों के प्रति चेतना जगाई।

आजादी के बाद गांधी चाहते थे कि शासन समाज के

अंतिम व्यक्ति की आवाज सुने और रचनात्मक कार्यक्रम को प्राथमिकता दे। संविधान ने नागरिकों को न्यायिक उपचार के साथ शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति का अधिकार भी दिया।

लेकिन व्यवस्था की सीमाओं से आकांक्षाएं पूरी न होने पर लोगों ने आंदोलनों का रुख किया। डॉ. राम मनोहर लोहिया के कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ और %अंग्रेजी हटाओ% जैसे आंदोलनों ने आजाद भारत में राजनीतिक आंदोलनों को नई धार दी। इतिहास राजनीतिक आंदोलनों को पहली बड़ी सफलता छात्रों की भागीदारी से मिली। 1973–74 के गुजरात नव–निर्माण आंदोलन ने भ्रष्टाचार और महंगाई के विरोध में चिमनभाई पटेल सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर किया।

इससे उत्साहित बिहार के छात्रों ने 1974 में जयप्रकाश नारायण से राज्य के कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। बाद में यही आंदोलन इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध व्यापक जनआंदोलन में बदल गया। जेपी ने पटना के गांधी मैदान से %संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान किया। आंदोलन के दबाव में आपातकाल लगा, विपक्षी नेता जेल गए और प्रेस पर पाबंदियां लगीं—यह भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना गया। 1977 में पहली बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना व लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन हेतु इस आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व रहा। ज़्यादा जाने सामाजिक मुद्दे और हिमायत लोग और समाज शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका

लेकिन पूरी तरह खुला है इसे खत्म करने का रास्ता चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा आदि के नेतृत्व में उत्तराखंड का %चिपको आंदोलन’

(1973) जंगलों व पर्यावरण संरक्षण की व्यापक जनचेतना का माध्यम बना। नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985) मेधा पाटकर के नेतृत्व में सरदार सरोवर बांध से प्रभावित किसानों, आदिवासियों और विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू हुआ। आंदोलन ने बड़े बांधों के सामाजिक–पर्यावरणीय प्रभावों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ी। बांध

1973–74 के गुजरात नव–निर्माण

आंदोलन ने भ्रष्टाचार और महंगाई के

विरोध में चिमनभाई पटेल सरकार को

इस्तीफा देने पर मजबूर किया। इससे

उत्साहित बिहार के छात्रों ने 1974 में

जयप्रकाश नारायण से राज्य के

कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध

आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह

किया। बाद में यही आंदोलन इंदिरा

गांधी सरकार के विरुद्ध व्यापक

जनआंदोलन में बदल गया। जेपी ने

पटना के गांधी मैदान से %संपूर्ण क्रांति’

का आह्वान किया। आंदोलन के दबाव

में आपातकाल लगा, विपक्षी नेता जेल

गए और प्रेस पर पाबंदियां लगीं—यह

भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय

माना गया।

निर्माण रोकने में असफल रहने पर भी आंदोलन ने सरकारों को विस्थापितों के मुआवजे व पुनर्वास के लिए दबाव में लाया और यह सवाल उठाया कि विकास की कीमत कौन चुकाए तथा प्रभावितों के अधिकार कैसे सुरक्षित हों?

वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग (1990) लागू करने के विरोध में छात्रों का व्यापक आंदोलन हुआ, जिसमें राजीव गोस्वामी सहित कुछ युवाओं ने आत्मदाह का प्रयास

किया। मंडल के साथ उभरी %कमंडल’ की राजनीति ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक धुवीकरण को भी गहरा किया। महिला आंदोलनों ने दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने के साथ समान अधिकारों की मांग की। मुस्लिम महिलाओं के आंदोलनों ने गुजारा भत्ता, तीन तलाक और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श में

1973–74 के गुजरात नव–निर्माण

आंदोलन ने भ्रष्टाचार और महंगाई के

विरोध में चिमनभाई पटेल सरकार को

इस्तीफा देने पर मजबूर किया। इससे

उत्साहित बिहार के छात्रों ने 1974 में

जयप्रकाश नारायण से राज्य के

कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध

आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह

किया। बाद में यही आंदोलन इंदिरा

गांधी सरकार के विरुद्ध व्यापक

जनआंदोलन में बदल गया। जेपी ने

पटना के गांधी मैदान से %संपूर्ण क्रांति’

का आह्वान किया। आंदोलन के दबाव

में आपातकाल लगा, विपक्षी नेता जेल

गए और प्रेस पर पाबंदियां लगीं—यह

भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय

प्रमुखता दी

श्रमिक आंदोलनों ने न्यायपूर्ण वेतन व श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भाषा के संसाधन ज़्यादा जानें खेल जगत अपडेट समाचार पत्र प्रकाशन भौगोलिक संदर्भ इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के शुरुआती वर्षों में हुए निर्भया आंदोलन ने सरकार को यौन अपराधों के विरुद्ध कड़े कानून बनाने के लिए विवश किया तो अज्ञा हजारे के नेतृत्व में चले भ्रष्टाचार–विरोधी आंदोलन

ने भ्रष्टाचार और लोकपाल के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया।

इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभार से लेकर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार को मिली राजनीतिक चुनौती तक, भारतीय राजनीति में

आंदोलनों के प्रभाव का एक नया दौर दिखाई दिया। आज देश में फिर आंदोलन का माहौल बन रहा है। 2020–21 में तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध चला लंबा किसान आंदोलन सरकार को कानून वापस लेने पर विवश कर गया और आंदोलनों की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण उदाहरण बना। इसके बाद %काकरोच जनता पार्टी’ के बैनर तले नई पीढ़ी परीक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर–मंतर पर एकत्रित हुई। गांधीवादी सोनम वांगचुक ने आंदोलन के समर्थन में 26 दिन की भूख हड़ताल की। अंततः 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने आंदोलनकारियों की अन्य मांगें भी स्वीकार कर लीं। जेन जी के आंदोलनों की विशेषता सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्क और त्वरित जनसंचार का प्रभावी इस्तेमाल है। विकेंद्रीकृत नेतृत्व ने युवाओं को तेजी से जोड़ा, जो पारंपरिक दलों की केंद्रीकृत राजनीति से भिन्न है, और भविष्य में दलों की कार्यप्रणाली, चुनावी रणनीतियों व सामाजिक–आर्थिक विमर्श को प्रभावित कर सकता है। जेन जी का प्रभाव केवल युवाओं तक सीमित नहीं दिखता; प्रौढ़ मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करने की उसकी क्षमता सत्तारूढ़ दलों के लिए भविष्य की बड़ी राजनीतिक चिंता बन सकती है। राजनीति

पूर्ववर्ती आंदोलनों की तरह यह छात्र आंदोलन भी कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर

शांतिपूर्ण और गांधीवादी सत्याग्रह की तरह अहिंसक रहा तथा व्यवस्था की कमियों को सुधारने के लिए आगे आया। वर्तमान निराशाजनक राजनीतिक माहौल में जेन जी के इन निडर युवाओं ने बदलाव की उ मीद जगाई है।

इस आंदोलन ने आलोचकों और प्रदर्शनकारियों को भारत–विरोधी ताकतों से पोषित’ बताने वाली सत्ता पक्ष की पुरानी बयानबाजी की धार भी कुछ कुंद् की है। इस आंदोलन को लेकर कुछ सवाल और आशंकाएं भी हैं—क्या लड़कियों के लिए भी अभद्र भाषा उतनी ही स्वीकार्य हो सकती है जितनी लड़कों के लिए? क्या सरकार को छात्रों से पहले संवाद नहीं करना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल—क्या जेन जी स्थापित राजनीतिक दलों को पीछे धकेलकर सत्ता तक पहुंच पाएगी? वर्तमान के घाघ राजनीतिज्ञ सोशल मीडिया पर उससे मुकाबला कैसे करेंगे और उसकी अनुभवहीनता भविष्य में शासन के लिए चुनौती बनेगी? भारत की स्वतंत्रता का अहिंसक संघर्ष अनेक देशों के लिए उपनिवेशवाद से मुक्ति का उदाहरण बना, और गांधी की अहिंसा व सत्याग्रह आज भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा है। लोकतंत्र में आंदोलनों का होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि नागरिक चेतना और शासन को जवाबदेह बनाए रखने की जीवंत शक्ति है। आंदोलनों की परंपरा बताती है कि स्वराज और लोकतंत्र चुनावों से नहीं, बल्कि नागरिकों की सतत भागीदारी और प्रतिरोध से जीवित रहते हैं।



रास्ता मुश्किल

अनौपचारिक रोज़गार की ओर धकेल रहे हैं। अक्सर, युवा खुद को ऐसी नौकरियों में पाते हैं जो उनकी योग्यता या आकांक्षाओं से मेल नहीं खातीं, या जो आय की असुरक्षा को कम करने के लिए ज़रूरी लेबर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहती हैं। मुआवजे और लाभ खास तौर पर चिंताजनक बात मध्यम–कौशल वाली नौकरियों में कमी है, जो कभी सेकेंडरी स्कूल या टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुरक्षित विकल्प हुआ करती थीं। युवाओं के लिए श्रम बाजार के इन प्रतिकूल नतीजों के साथ–साथ, एआई के बारे में भी चर्चा बढ़ रही है। हालांकि नौकरियों पर इसके प्रभाव के सबूत अभी भी अनिश्चित हैं, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए और रिपोर्ट में बताए गए जोखिमों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। युवाओं में चिंता का स्तर बहुत ज़्यादा है। श्रम बाजार में अस्थिरता से जुड़े नुकसानों को देखते हुए – जिनमें युवाओं की भलाई और लंबे समय में उनकी उत्पादकता और कमाई की संभावनाओं पर असर शामिल है – यह रिपोर्ट कार्रवाई करने का एक आह्वान है। ज़्यादा

जानें नौकरी सूची अखबार प्रादेशिक समाचार जहां युवाओं के रोज़गार में ठहराव आया है या कमी आई है, वहीं वयस्कों के रोज़गार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर युवाओं की बेरोज़गारी दर 2023 में 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 12.4 प्रतिशत हो गई, जबकि वयस्कों (25 वर्ष और उससे अधिक उम्र) की दर 3.7 प्रतिशत से घटकर 3.6 प्रतिशत हो गई। इन अलग–अलग रुझानों के कारण युवाओं और वयस्कों की बेरोज़गारी दरों का अनुपात बढ़ गया है (2025 में यह 3.4 था), जो यह संकेत देता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए युवा टैलेंट को काम पर रखने में मुश्किलें बढ़ रही हैं। पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ़्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी एशिया में युवाओं और वयस्कों की बेरोज़गारी दरों का अनुपात बढ़ा है। गणित यह रोज़गार (वेतन–आधारित रोज़गार) से जुड़ी नीतियों के क्षेत्र में और अधिक काम करने की तत्काल आवश्यकता और मज़दूरों व सामाजिक सुरक्षा के बारे में एक स्पष्ट संदेश देता है, ताकि युवाओं को भरोसा दिलाया जा सके कि उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है।



एमबीए करने रुस गए बेटे का ताबूत में लौटा 2 भाई, 1 पत्नी और अब गूंजी किलकारी... शव, दलालों ने ऐसे धकेला था मौत के मुंह में

रेवाड़ी। गुरुग्राम से सटे हरियाणा के रेवाड़ी जिले के काटुवास गांव में शुक्रवार को चीख-पुकार मच गई। जिस बेटे को पिता ने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगाकर सुनहरे भविष्य के लिए रुस भेजा था, उसका शव जब लकड़ी के ताबूत में लिपटकर गांव पहुंचा तो हर आंख नम हो गई। 22 वर्षीय अंशु रुस में एमबीए की पढ़ाई करने गया था, लेकिन दलालों के धोखे का शिकार होकर वह रुस—यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की तरफ से लड़ने को मजबूर हो गया और वहीं मौत के मुंह में समा गया। अंशु का शव जब श्मशान घाट पहुंचा, तो लकड़ी के भारी ताबूत को खोलने के लिए कटर मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा। ताबूत खुलते ही अंदर का नजारा देखकर परिवार वालों का कलेजा फट गया। बॉक्स में अंशु के शव के साथ उसकी



रूसी सेना की वर्दी और जूते भी भेजे गए थे। नम आंखों और भारी मन से बड़े भाई मोहित ने अपने लाडले छोटे भाई की चिता को मुखाग्नि दी। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी रोष है। लोगों का साफ कहना है कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि उन लालची दलालों की रची गई खौफनाक साजिश है जिन्होंने शिक्षा के नाम पर एक होनहार छात्र को मौत के मोर्चे पर झोंक दिया। परिवहन विभाग में कार्यरत अंशु के पिता राकेश

कुमार ने बताया कि उनका बेटा बीए पास करने के बाद एमबीए करने का सपना लेकर 30 अप्रैल 2025 को स्टडी वीजा पर रुस गया था। वहां उसने कुछ महीने कॉलेज में पढ़ाई भी की, लेकिन इसके बाद वह शातिर दलालों के जाल में फंस गया। दलालों ने अंशु की पढ़ाई छुड़वाकर सितंबर 2025 में उसे जबरदस्ती रूसी सेना में भर्ती करा दिया। अंशु ने आखिरी बार 18 अक्टूबर 2025 को घर पर बात की थी। उस वक्त उसने अपने पिता को

बताया था कि उसे यूक्रेन युद्ध की फर्स्ट लाइन (मौत के मोर्चे) में भेजा जा रहा है और अब कुछ दिनों तक उसकी बात नहीं हो पाएगी। परिवार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि फोन पर हुई उस आखिरी बातचीत के कुछ समय बाद ही अंशु की मौत हो चुकी थी। परिजन करीब छह महीने तक अपने बेटे की राह देखते रहे। इस बीच 2 अप्रैल 2026 को परिवार ने देश के विदेश मंत्री से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। इसके ठीक दो दिन बाद, 4 अप्रैल को रुस के मॉस्को से पिता राकेश कुमार के पास एक मनहूस फोन आया। उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और शव मिलने के बाद उसे भारत भेजने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा। 16 अप्रैल को सूचना मिली कि शव दिल्ली एयरपोर्ट आ रहा है, जिसके बाद शुक्रवार सुबह शव लेने के बाद गांव

के श्मशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तीन भाई—बहनों में सबसे छोटा अंशु पूरे घर का लाडला था। पिता राकेश कुमार की पत्नी का काफी समय पहले ही देहांत हो चुका था, ऐसे में पिता ने ही अपनी सारी जमा—पूंजी लगाकर बेटे को बड़ा आदमी बनने के लिए विदेश भेजा था। आज उस घर में सिर्फ अंशु की यादें और रुस से आया उसका ताबूत ही बचा है। इस दर्दनाक घटना के बाद काटुवास के ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि मासूम युवाओं को पढ़ाई के बहाने युद्ध में धकेलने वाले दलालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। खौफ की बात यह भी है कि रुस गए हरियाणा के सात अन्य युवक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी सलामती को लेकर उनके परिवार खौफ में जी रहे हैं।

सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र से एक ऐसी अनोखी शादी की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। यहां के एक गांव में रहने वाले दो सगे भाइयों, कपिल और प्रदीप, ने स्थानीय परंपराओं का पालन करते हुए बीते साल जुलाई 2025 में एक ही महिला सुनीता के साथ सात फेरे लिए थे। इस शादी के करीब 10 महीने बाद अब इस परिवार में एक नन्हीं परी की किलकारी गूंजी है। सुनीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है, जिसके बाद से ही परिवार को लोगों की बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसा सवाल भी उठ खड़ा हुआ है जिसने इंटरनेट पर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा और कौतूहल इसी बात को लेकर है कि इस बच्ची का ‘वास्तविक पिता’ किसे माना जाएगा और सरकारी दस्तावेजों या जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) में किस भाई का नाम दर्ज होगा। आम लोगों के लिए यह उलझन भले ही बड़ी हो, लेकिन इस इलाके की सदियों पुरानी परंपरा के पास इसका सीधा जवाब है। स्थानीय मान्यताओं और सामाजिक नियमों के अनुसार, परिवार के बड़े भाई को ही इस नन्हीं बच्ची का आधिकारिक पिता माना जाएगा। सुनने में भले ही यह आधुनिक समाज

को अजीब लगे, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इस तरह की शादियों को स्थानीय स्तर पर ‘फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री’ (एक महिला का कई भाइयों से विवाह) कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य परिवार की खेती योग्य सीमित जमीन और संपत्ति के बंटवारे को रोकना तथा पूरे कुनबे को एक साथ मजबूती से जोड़े रखना रहा है। भारतीय कानून में इस तरह के बहुविवाह या बहुपति प्रथा को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में कागजी कार्रवाई और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए बड़े भाई को ही महिला का कानूनी पति माना जाता है। इसी आधार पर बच्चों के कागजातों में भी बड़े भाई का ही नाम पिता के तौर पर दर्ज होता है, भले ही बच्चे का बायोलॉजिकल पिता कोई भी हो। इस अनोखे वैवाहिक रिश्ते में पत्नी दोनों भाइयों के साथ एक ही छत के नीचे रहती है और यह फैसला पूरी तरह से महिला का होता है कि वह कब किसके साथ समय बिताएगी। इस दिलचस्प और प्राचीन प्रथा की गहराई को समझने के लिए हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस परमार ने साल 1975 में ‘बहुपति प्रथा’ पर एक विस्तार से किताब भी लिखी थी, जिसमें पहाड़ों के इस अनोखे सामाजिक ताने—बाने की पूरी जानकारी दी गई है।

डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने जालंधर के लिए प्रमुख विकास प्राथमिकताओं की रूपरेखा पर डाला प्रकाश

जालंधर। डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने जालंधर जिले को विकास की दृष्टि से एक प्रगतिशील जिले में बदलने के लिए अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा साझा की। आज यहां जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कृषि, बुनियादी ढांचे और बेहतर प्रशासन पर केंद्रित व्यापक रणनीति पर प्रकाश डाला। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता चल रहे गेहूं खरीद सीजन को उचित और निर्विघ्न ढंग से निपटाना है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा पहले ही जिले भर की मंडियों में गेहूं की निर्विघ्न खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। किसानों को पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए श्री वालिया ने कहा कि किसानों को अपनी फसल की बिक्री में कोई दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी। बुनियादी ढांचे के विकास को एक और प्रमुख प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिक

सेवाओं को मजबूत करने और चल रहे विकास प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कोई कसर बाकी नहीं रहने दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब सरकार की लोक कल्याण योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने की महत्वता पर जोर दिया। उन्होंने विशेष तौर पर ‘मुख्यमंत्री मावां—धीया सत्कार’ योजना और ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों का उचित रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित बनाया जाएगा। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डिप्टी कमिश्नर ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में किए जा रहे योगदान की सराहना की, जिन्होंने समय पर निपटारे के लिए जन समस्याओं को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई जा रही है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण के शाश्वत प्रतीक युगपुरुष आद्य शंकराचार्य

भारतीय वांग्मय के आकाश में आद्य गुरु शंकराचार्य एक ऐसे प्रदीप्त भास्कर हैं, जिन्होंने अल्पायु में ही अपनी मेधा से दिग्दगंत को आलोकित किया। बैशाख शुक्ल चतुर्थीको उनका प्रादुर्भाव मात्र एक घटना नहीं, अपितु क्षरणोन्मुख सनातन धर्म के पुनरुत्थान का दैवीय अभियान था।शंकराचार्य का आध्यात्मिक दर्शन “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः”के सूत्र में समाहित है। उन्होंने उपनिषदों की दुरुह व्याख्याओं को प्रस्थानत्रयीपर भाष्य लिखकर तार्किक परिपक्वता प्रदान की। पौराणिक दृष्टि से वे भगवान शंकर के अंशावतार माने जाते हैं, जिन्होंने षष्मतकी स्थापना कर विभक्त शैव, वैष्णव और शाक्त मतों को एक ही अद्वैत धरातल पर प्रतिष्ठित किया। उनका दर्शन शुष्क बौद्धिकता नहीं, अपितु आत्मानुभूति का वह शिखर है जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद तिरोहित हो जाता है।शंकराचार्य ने भारत की भौगोलिक सीमाओं को आध्यात्मिक सूत्र में पिरोने हेतु चर्तुदिक चार पीठों की स्थापना की— शृंगेरी, पुरी, द्वारका और ज्योतिर्मठ। यह मात्र धार्मिक केंद्र नहीं, अपितु भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता के रक्षक स्तंभ थे। उन्होंने दशनामी संन्यासपद्धति का गठन कर बिखरे हुए साधु—संतों को एक अनुशासित व्यवस्था में आबद्ध किया, जिससे धर्म की रक्षा हेतु एक वैचारिक सेना तैयार हुई।यद्यपि शंकराचार्य प्रकांड पंडित थे, उनके सामाजिक विचार अत्यंत उदार और समतावादी थे। काशी के मणिकर्णिका घाट पर चांडालके रूप में साक्षात् शिव से संवाद कर उन्होंने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मज्ञान जाति और वर्ण की सीमाओं से परे है। मनीषा पंचकम्ह्सका जीवंत प्रमाण है। उन्होंने शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित कर हिंसा के स्थान पर संवाद और तर्क को सत्य अन्वेषण का माध्यम बनाया। आधुनिक ऐतिहासिक विमर्शों में उनके कालखंड को लेकर शोध निरंतर जारी हैं। केंदारनाथ में उनकी समाधि का जीर्णोद्धार और देश भर के प्राचीन मंदिरों, यथा— बदरीनाथ, कामाख्या, और कांची में उनके द्वारा स्थापित श्रीचक्र एवं प्रतिमाएं उनके ऐतिहासिक अस्तित्व और प्रभाव की पुरातात्विक पुष्टि करती हैं। आदि गुरु द्वारा पुनर्जीवित किए गए तीर्थ आज भी भारत की अखंडता के जीवंत साक्ष्य हैं। शंकराचार्य

का जीवन चरैवेति—चरैवेतिका साक्षात उदाहरण है। उन्होंने विखंडित समाज को एकता के सूत्र में पिरोया और ज्ञान के मरुस्थल में भक्ति एवं अद्वैत की मंदाकिनी प्रवाहित की। उनकी जयंती पर हमारा वास्तविक नमन उनके अद्वैतभाव को अपने आचरण में उतारना ही होगा।आचार्य शंकर ने केवल दार्शनिक एवं सांगठनिक नवोन्मेष संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उन सिद्धांतों के संरक्षण हेतु एक अमेद्य सांगठनिक ढांचे का निर्माण किया। उन्होंने संन्यास की बिखरी हुई परंपराओं को दशनामी (गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती) के अंतर्गत वर्गीकृत कर उसे एक सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया।यह वर्गीकरण केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि इसके पीछे परिव्राजक (निरंतर भ्रमणशील संन्यासी) की संकल्पना थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ज्ञान केवल हिमालय की गुफाओं या मठों तक सीमित न रहे, अपितु वन, पर्वत और तीर्थों के माध्यम से जन—सामान्य तक प्रवाहित होता रहे।इन दस नामों के माध्यम से उन्होंने भारत की संपूर्ण भौगोलिक संपदा को अध्यात्म से जोड़ दिया। यह विश्व का संभवतः पहला ऐसा सांगठनिक प्रयास था, जहां संन्यास को व्यक्तिगत मोक्ष के साथ—साथ लोक संग्रह (सामाजिक कल्याण) का उत्तरदायित्व सौंपा गया।भारतीय दर्शन में किसी भी मत को स्थापित मानने हेतु उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भगवद्गीता (प्रस्थानत्रयी) पर भाष्य करना अनिवार्य था। आचार्य शंकर के भाष्य केवल व्याख्याएं नहीं, अपितु तार्किक क्रांति थे। यह राष्ट्र चेतना का आह्वान था। उपनिषद भाष्य (श्रुति प्रस्थान) के माध्यम से आचार्य ने अविद्या के आवरण को हटाकर जीव और ब्रह्म की तात्विक एकता को सिद्ध किया। उन्होंने स्थापित किया कि ज्ञान कर्म का अंग नहीं, अपितु स्वतंत्र फलदायी है।ब्रह्मसूत्र भाष्य (शारीरिक मीमांसा) के माध्यम से उन्होंने तर्क और युक्ति के आधार पर द्वैतवादी मतों का खंडन किया। यह उनके बौद्धिक कौशल की पराकाष्ठा है, जहां वे अत्यंत सूक्ष्म सूत्रों की व्याख्या करते हुए चिन्मात्र सत्ता को प्रदीप्त करते हैं। शंकर ने गीता भाष्य के माध्यम से निष्काम कर्म को चित्त शुद्धि का साधन बताते हुए उसे ज्ञान की प्राप्ति का सोपान सिद्ध किया।प्रायः विद्वान शंकर को केवल निषेधात्मक

(नेति—नेति) दार्शनिक मानते हैं, किंतु उनके भाष्यों का सूक्ष्म अवलोकन यह प्रकट करता है कि वे अस्वीकार नहीं बल्कि समावेश के पक्षधर थे। उन्होंने बौद्ध शून्यवाद की तार्किकता को तो स्वीकार किया, परंतु उसे उपनिषदों के पूर्णत्व(ब्रह्म) से मंडित कर दिया।आचार्य का संन्यास संप्रदाय कवच था और प्रस्थानत्रयी भाष्य प्रकाश। कवच ने सनातन संस्कृति की रक्षा की और प्रकाश ने भ्रांतियों के अंधकार को मिटाया। उनके भाष्यों में विद्यमान सत्य आज भी आधुनिक भौतिक विज्ञान के क्वांटम फील्ड थ्योरी जैसे सिद्धांतों को चुनौती देता प्रतीत होता है। आद्य गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चतुष्पीठ केवल मठ नहीं, बल्कि चेतना के केंद्र हैं। प्रत्येक पीठ को एक विशिष्ट वेद, एक महावाक्य और एक विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया, जो उनकी सूक्ष्म सांगठनिक दृष्टि को दर्शाता है।पूर्व के पुरी —गोवर्धन मठ) में ऋग्वेद की प्र्धानता है। इसका महावाक्य प्रज्ञानं ब्रह्म (बोध ही ब्रह्म है) है। यह पीठ चेतना के शुद्ध स्वरूप को रेखांकित करती है।पश्चिम के द्वारका —शारदा मठ में सामवेद का वर्चस्व है। महावाक्य तत्त्वमसि (वह तुम ही हो) गुरु—शिष्य परंपरा के उपदेशात्मक पक्ष को पुष्ट करता है।उत्तर के बदरिकाश्रम —ज्योतिर्मठ में अथर्ववेद मुख्य हैं। महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म (यह आत्मा ही ब्रह्म है) अंतर्मुखी साधना का प्रतीक है।दक्षिण के शृंगेरी —शारदा पीठ में यजुर्वेद का प्राधान्य है। महावाक्य अहं ब्रह्मास्मि (मैं ही ब्रह्म हूँ) साधक की अंतिम अनुभूति का उद्घोष है।इन पीठों के माध्यम से आचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का कोई भी कोना वेद—विहीन न रहे। गोत्र और संप्रदाय के विभाजन द्वारा उन्होंने संन्यासियों के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट किया, जिससे सांस्कृतिक अतिक्रमण की संभावना समाप्त हो गई।आज का विज्ञान जहां पदार्थ की गहराइयों में उतरकर उसे ऊर्जा और अंततः एक क्षेत्र के रूप में देख रहा है, आचार्य शंकर ने सहस्राब्दियों पूर्व इसे माया और ब्रह्म के रूप में परिभाषित कर दिया था।क्वांटम सुपरपोजिशन भौतिकी कहती है कि जब तक पर्यवेक्षक न हो, कण की स्थिति अनिश्चित है। शंकराचार्य का मायावाद भी यही कहता है— संसार प्रतीत तो होता है (व्यावहारिक सत्ता), किन्तु परम सत्य (पारमार्थिक सत्ता) के धरातल पर उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।ब्रह्म वह अविनाशी तत्व है जो न घटता

है, न बढ़ता है। विज्ञान के ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत अद्वैत के पूर्वमदः पूर्वमिदम् का ही आधुनिक भौतिक अनुवाद है।वैज्ञानिक जिस एकीकृत क्षेत्र (थ्योरी ऑफ एवरीथिंग) की खोज में हैं, अद्वैत वेदान्त वह खोज पूरी कर चुका है। शंकर के अनुसार, विविधता केवल नाम और रूप की है, मूल तत्व चिदाकाश एक ही है। शंकराचार्य का दर्शन केवल मध्यकालीन समाधान नहीं था, बल्कि वह भविष्य का विज्ञान है। उनके पीठों ने जहां भारत को भौगोलिक सूत्र में बांधा, वहीं उनके अद्वैत दर्शन ने वैश्विक मेधा को वह तार्किक आधार दिया, जहां धर्म और विज्ञान का विरोध समाप्त होकर एक पूर्ण सत्य का उदय होता है।आद्य गुरु शंकराचार्य के स्तोत्र साहित्य (विशेषतः सौन्दर्य लहरी) में निहित तांत्रिक रहस्यों एवं समकालीन वैश्विक संकटों के निराकरण में अद्वैत की भूमिका, पराशक्ति का वांग्मय विग्रह एवं अद्वैत की वैश्विक उपादेयता पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि आचार्य शंकर अपने भाष्यों में तो कठोर तर्कवादी (शुष्क वेदान्ती) प्रतीत होते हैं, वहीं अपने स्तोत्र साहित्य में वे परम भावुक भक्त और उच्च कोटि के श्रीविद्या उपासक के रूप में उभरते हैं।सौन्दर्य लहरी के प्रथम श्लोक —शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्, में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शक्ति के बिना शिव स्पन्दनहीन (शववत) हैं। यह दर्शन का वह मौलिक विन्दु है जहां वेदान्त और तन्त्र का मिलन होता है। यहां माया केवल बंधन नहीं, बल्कि ललिता महात्रिपुरसुंदरी के रूप में सृजन की ईश्वरीय सामर्थ्य है।उनके स्तोत्रों में मूलाधार से सहस्रार तक के षट्चक्र भेदन का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। यह सिद्ध करता है कि आचार्य के लिए ब्रह्म केवल बौद्धिक अवधारणा नहीं, बल्कि शरीर के भीतर अनुभूत होने वाली कुण्डलिनी शक्ति की ऊर्ध्वगति है। कुण्डलिनी योग का प्रतिपादन कर उन्होंने श्रीयंत्र (श्रीचक्र) के नौ चक्रों को ब्रह्मांड के नौ स्तरों का प्रतीक मानकर बाह्य और आंतरिक जगत का अभेद स्थापित किया। आज का विश्व विखंडन और पहचान के संकट से जूझ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अद्वैत दर्शन एक ग्लोबल एथिक्स (वैश्विक नीतिशास्त्र) प्रस्तुत करता है।



पुरी के रेस्टोरेंट में मैसूर के ट्रिस्ट कपल से कथित मारपीट, खाने में बाल मिलने से शुरू हुआ विवाद

पुरी २७/०९ (संवाददाता): ओडिशा के पुरी में स्वर्गद्वार के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में मैसूर से आए एक पर्यटक दंपति के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। खाने में बाल मिलने की शिकायत और उसके बाद बिल के भुगतान को लेकर शुरू हुआ विवाद कथित मारपीट तक पहुंच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुरी के एसपी प्रतीक सिंह के मुताबिक, मैसूर से आया पर्यटक जोड़ा बुधवार शाम स्वर्गद्वार के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा था। खाना परोसे जाने के बाद दंपति ने एक डिश में बाल मिलने की शिकायत रेस्टोरेंट प्रबंधन से की। शिकायत मिलने पर रेस्टोरेंट की ओर से वह डिश बदलकर दूसरी डिश उपलब्ध कराई गई।

बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद जब बिल आया तो दंपति ने उस डिश के पैसे लिए जाने पर सवाल उठाया, जिसे बाल मिलने के कारण वापस कर दिया गया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और पर्यटक दंपति के साथ मारपीट की गई। खाने में बाल मिलने पर की थी शिकायत पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत खाने की गुणवत्ता को लेकर हुई। पर्यटक दंपति ने रेस्टोरेंट कर्मचारियों से कहा कि उन्हें परोसी गई एक डिश में बाल मिला है। इसके बाद उन्होंने डिश वापस कर दी। रेस्टोरेंट प्रबंधन ने शिकायत के बाद उन्हें दूसरी डिश उपलब्ध कराई। शुरुआत में मामला यहीं समाप्त होता दिखाई दिया, लेकिन बाद में बिल के भुगतान के समय दोनों पक्षों के बीच फिर विवाद हो

गया। दंपति ने सवाल किया कि जिस खाने को उन्होंने बाल मिलने के कारण वापस कर दिया था, उसके लिए उनसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। इसी बात पर रेस्टोरेंट मैनेजर और पर्यटकों के बीच बहस होने की बात सामने आई है। बायोलाॅजी किट आजमाएँ बिल को लेकर बढ़ा विवाद , दृष्टांत ऋद्धुस - महानदी उफान पर हीराकुंड के 16 गेट खुले खाने का बिल सामने आने के बाद पर्यटक दंपति ने कथित रूप से आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि खराब गुणवत्ता की शिकायत के बाद लौटाई गई डिश के पैसे बिल में नहीं जोड़े जाने चाहिए थे। इस पर रेस्टोरेंट प्रबंधन और पर्यटकों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे बहस में बदल गई। आरोप है कि बहस के दौरान स्थिति बिगड़ गई और मामला हाथपाई तक पहुंच गया। हालांकि घटना के दौरान किसने पहले मारपीट शुरू की और विवाद किस तरह



बढ़ा, इन परिस्थितियों की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस संबंधित लोगों के बयान और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम स्पष्ट करने का प्रयास कर रही है। मैसूर से आए दंपति ने आरोप लगाया है कि विवाद बढ़ने के बाद उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई गई। ट्रैवल गाइड पढ़ें पर्यटकों के साथ हुई कथित मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मारपीट के आरोप शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से लगाए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के लिए जि मेदारी और पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने दर्ज किया मामला पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है और जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि खाने के बिल को लेकर

शुरू हुआ विवाद किस परिस्थिति में कथित मारपीट में बदल गया। जांच के दौरान रेस्टोरेंट में मौजूद कर्मचारियों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा यदि रेस्टोरेंट या आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो उनको रिकॉर्डिंग भी घटनाक्रम को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पुलिस दोनों पक्षों का बयान लेकर आरोपों की सत्यता की जांच करेगी। जांच के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। स्वर्गद्वार के पास हुई घटना यह घटना पुरी के स्वर्गद्वार के पास हुई है। यह क्षेत्र शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाकों में शामिल है। बड़ी सं या में पर्यटक और श्रद्धालु इस क्षेत्र में पहुंचते हैं। आसपास होटल, लॉज और खाने-पीने के कई प्रतिष्ठान मौजूद हैं। सुरक्षा हेल्पलाइन खोजें पुरी देश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। जगन्नाथ

मंदिर और समुद्र तट के कारण देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी सं या में लोग यहां आते हैं। ऐसे में किसी पर्यटक के साथ विवाद या कथित मारपीट की घटना सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी पुलिस पुलिस अब खाने में बाल मिलने की शिकायत से लेकर बिल के विवाद और कथित मारपीट तक पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। यह भी देखा जाएगा कि विवाद के दौरान कौन-कौन लोग मौके पर मौजूद थे और उनकी क्या भूमिका रही। दंपति की शिकायत के साथ रेस्टोरेंट प्रबंधन का पक्ष भी जांच का हिस्सा होगा। किसी एक पक्ष के आरोप के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करेगी। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने की स्थिति में उससे यह पता

लगाने में मदद मिल सकती है कि विवाद कैसे शुरू हुआ और मारपीट के आरोपों के दौरान मौके पर क्या हुआ था। जांच के बाद साफ होगी स्थिति फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्यटक दंपति द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर निर्भर करेगी। खाने में बाल मिलने की शिकायत से शुरू हुआ यह विवाद बिल के भुगतान के सवाल पर बढ़ा और आखिरकार पुलिस तक पहुंच गया। अब पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने लाने की जि मेदारी है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि रेस्टोरेंट में पर्यटक दंपति के साथ वास्तव में किन परिस्थितियों में कथित मारपीट हुई और इसके लिए कौन जि मेदार था।

ओडिशा डीजीपी नियुक्ति मामले में सुको में विवाद, साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मांगी माफी

नई दिल्ली/भुवनेश्वर २७/०९ (संवाददाता): ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन की भूमिका को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य की टिप्पणी के एक दिन बाद गुरुवार को साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में माफी मांगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश सिंह फैसले में छलक नियुक्ति को लेकर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन से जुड़ा है। कानून प्रवर्तन कानूनी कोर्ट और न्यायपालिका विवाद की सुनवाई के दौरान शुरू हुआ था। एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने अमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन की दलीलों को लेकर कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे वह याचिकाकर्ता की ओर से मामला पेश कर रहे हों।

रामचंद्रन ने इस टिप्पणी पर गंभीर आपत्ति जताई और इसे वापस लेने की मांग की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ कर रही है। अदालत के सामने ओडिशा सरकार द्वारा DGP नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न सवाल विचाराधीन हैं। दृष्टांत ऋद्धुस - स्ट्रुक्चरविवाद के बीच चुनाव आयोग की बैठक, आयोग बोला- सभी फैसले सर्वस मति से लिए गए रामचंद्रन ने टिप्पणी पर जताई कड़ी आपत्ति एडवोकेट जनरल की टिप्पणी के बाद राजू रामचंद्रन ने कहा कि यदि इस तरह का आरोप रिकॉर्ड पर रहने दिया जाता है तो उनके लिए इस मामले में अमिकस क्यूरी के रूप में आगे बने रहना मुश्किल होगा। रामचंद्रन ने अदालत के सामने अपनी करीब 50 वर्षों की कानूनी प्रैक्टिस का उल्लेख करते हुए कहा कि उन पर पहले कभी सुप्रीम कोर्ट

में अनुचित तरीके से व्यवहार करने जैसा आरोप नहीं लगाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमिकस क्यूरी के रूप में उनकी जि मेदारी अदालत की सहायता करना है, न कि किसी एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करना। रिपोर्ट के मुताबिक पीठ ने भी इस घटनाक्रम के दौरान हस्तक्षेप किया। अगले दिन तुषार मेहता ने मांगी माफी गुरुवार को मामले से जुड़े घटनाक्रम के दौरान साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रामचंद्रन से माफी मांगी। इस पर रामचंद्रन ने मेहता के कदम की सराहना करते हुए कहा कि यह उनकी उदारता है, जबकि वे स्वयं उस टिप्पणी में शामिल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर के रिकॉर्ड में इस मामले में साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य सहित संबंधित वकीलों की उपस्थिति दर्ज है। ओडिशा के अगले पुलिस महानिदेशक की चयन

और नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित है। याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी गई है और आरोप लगाया गया है कि यह प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है। राज्य सरकार ने इन मुद्दों पर अदालत से समक्ष अपना पक्ष रखा है और मामले पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। विवाद में पात्र IPS अधिकारियों की सूची और पैनल तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी उठाए गए हैं। अमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन ने अपनी प्रस्तुतियों में वरिष्ठ IPS अधिकारी सुसांत कुमार नाथ को पात्रता सूची से बाहर किए जाने, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और बाद में सूची में शामिल किए गए कुछ अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित मुद्दों पर सवाल उठाए थे। अमिकस क्यूरी ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल राजू रामचंद्रन को इस मामले में अदालत की सहायता के लिए अमिकस

क्यूरी नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और दलीलों में DGP चयन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित किया है। इससे पहले हुई सुनवाई में उन्होंने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुपालन से संबंधित सवाल रखे थे। विशेष रूप से पात्र अधिकारियों की सूची तैयार करने और कुछ अधिकारियों को शामिल या बाहर करने के आधार पर चर्चा हुई है। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें बुधवार को एडवोकेट जनरल और अमिकस क्यूरी के बीच तीखी बहस हुई। रामचंद्रन का कहना था कि अदालत की सहायता के लिए नियुक्त अमिकस के काम को किसी पक्ष की पैरवी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रकाश सिंह फैसले से जुड़ा है मामला ओडिशा DGP नियुक्ति का विवाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में जारी निर्देशों के संदर्भ में सुना जा रहा है।



राउरकेला २७/०९ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी, श्री आलोक वर्मा और सभी कार्यपालक निदेशकों ने मंथन समेलन कक्ष में आयोजित एक बैठक में ओडिशा समूह खान सहित आरएसपी में रिश्ततखोरी विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता की समीक्षा की। बैठक में मानक के प्रावधानों को पूरा करने के लिए उठाए गए उपायों पर सतर्कता विभाग द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। इनमें संवेदनशील विभागों द्वारा रिश्तत जोखिम मूल्यांकन, कर्मचारियों और व्यावसायिक

सहयोगियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, आंतरिक और बाहरी चैनलों के माध्यम से हितधारक संचार और व्यावसायिक सहयोगियों से रिश्ततखोरी विरोधी प्रतिबद्धताएं शामिल थीं। आंतरिक लेखा परीक्षा के निष्कर्ष और अनुपालन टीम की सिफारिशें भी प्रस्तुत की गईं। समीक्षा में निरंतर सुधार के प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिसमें अतिरिक्त कर्मचारी प्रशिक्षण, विभिन्न हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का एक वार्षिक कार्यक्रम और ज्ञान प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से एबीएमएस जानकारी का

व्यापक प्रसार शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य एबीएमएस ढांचे को मजबूत करना और आरएसपी और इसकी खानों में अखंडता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, नैतिक शासन के लिए सेल की प्रतिबद्धता और रिश्ततखोरी के लिए शून्य सहिष्णुता को मजबूत करना है। बैठक ने एक मजबूत रिश्ततखोरी विरोधी संस्कृति को बनाए रखने, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने और एक जि मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में संयंत्र की प्रतिष्ठा की रक्षा करने पर शीर्ष प्रबंधन के ज़ोर को रेखांकित किया।

पानी तेज बहाव में फंसी कार, दो घंटे तक अटकी रहीं दो जिंदगियां

भुवनेश्वर २७/०९ (संवाददाता): ओडिशा के मयूरभंज जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। ऊदाला थाना क्षेत्र के नहरापाड़ा गांव के पास सड़क पर बह रहे तेज पानी की चपेट में एक कार आ गई। देखते ही देखते कार बहकर पानी के बीच फंस गई। उसमें सवार दो लोग करीब दो घंटे तक अंदर फंसे रहे। बाद में ग्रामीणों ने कड़ी मशक़त कर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक दुष्मंत देसरी अपने एक साथी के साथ कार से नहरापाड़ा गांव जा रहे थे। रास्ते में बारिश के कारण सड़क के ऊपर से तेज र तार में पानी बह रहा था। दोनों कार से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि चालक वाहन को संभाल नहीं पाया। तेज बहाव में बहने लगी कार सड़क पार करने के दौरान अचानक पानी ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार सड़क से बहते हुए



कुछ दूरी पर जाकर पानी के बीच अटक गई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि दोनों लोग कार से सुरक्षित बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। आसपास पानी का तेज बहाव होने के कारण बाहर निकलने की कोशिश करना जोखिम भरा था। दोनों लोग कार के अंदर ही फंसे रहे और मदद का इंतजार करते रहे। समय बीतने के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। करीब दो घंटे तक दोनों पानी के बीच फंसी

कार में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। ग्रामीणों की पड़ी नजर कुछ समय बाद स्थानीय ग्रामीणों की नजर पानी के बीच फंसी कार पर पड़ी। कार में लोगों के मौजूद होने का पता चलते ही ग्रामीण मदद के लिए आगे आए। तेज बहाव के बावजूद लोगों ने सावधानी के साथ बचाव का प्रयास शुरू किया। काफी मशक़त के बाद ग्रामीण कार तक पहुंचे और उसे पानी से बाहर निकालने में

सफल रहे। इसके बाद कार में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। समय रहते मदद मिलने के कारण बड़ा हादसा टल गया। ओडिशा में बारिश के दौरान कई क्षेत्रों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने और सड़कों पर पानी बहने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे हालात में पानी से भरी सड़क पार करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। पानी की गहराई और बहाव का सही अंदाजा नहीं लगने पर वाहन कुछ ही सेकंड में नियंत्रण खो सकता है। मयूरभंज की घटना में भी सड़क पर बहते पानी ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से कार में सवार दोनों लोगों की जान बच गई। फिलहाल घटनास्थल की विस्तृत स्थिति, बचाए गए दोनों लोगों के स्वास्थ्य और कार को हुए नुकसान के संबंध में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

आरएसपी परिवार की बेटी स्वास्ती सिंह जापान में होने वाले 2026 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी

राउरकेला २७/०९ (संवाददाता): स्वास्ती सिंह, जो सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र के ऑक्सीजन प्लांट में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे श्री अमर सिंह और श्रीमती उमा देवी की बेटी हैं, जापान में होने वाले एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह युवा साइकिल चालक दो स्पर्धाओं - 4 किमी टीम पीछा और महिला मैडिसन - में हिस्सा लेंगी और देश के साथ-साथ अपने शहर की उ मीदों और सपनों को भी आगे बढ़ाएंगी। राउरकेला की साइकिलिंग प्रतिभा, स्वास्ती ने अपने समर्पण, अनुशासन और निरंतर प्रयासों के माध्यम से साइकिलिंग के क्षेत्र में अपने लिए एक जगह बनाई है। उन्होंने अब तक 20 से अधिक राष्ट्रीय पदक और चार अंतराष्ट्रीय पदक जीते हैं। दिसंबर 2025



में रुद्रपुर में आयोजित 77 वीं सीनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में, उन्हें तीन स्वर्ण पदक और दो रजत पदक जीतने के बाद दूनमेंट की %सर्वश्रेष्ठ महिला साइकिल चालक% का ताज पहनाया गया। उल्लेखनीय है कि स्वास्ती ने आरएसपी के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में अपने साइकिलिंग कौशल का स मान किया है। लगातार प्रशिक्षण और केंद्रित तैयारी के साथ, वह लगातार अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रगति

कर रही है, राउरकेला और ओडिशा को गौरव दिला रही है। एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनका चयन उनकी खेल यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अपनी बेटी की सफलता पर बोलेते हुए, गर्वित पिता श्री अमर सिंह कहते हैं, ऋमुझे अपनी बेटी को एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देखकर बहुत गर्व और खुशी हो रही है। मैं उन सभी के प्यार, समर्थन और आशीर्वाद

के लिए आभारी हूं जिन्होंने उनकी यात्रा के दौरान उन्हें प्रोत्साहित किया है। मैं विशेष रूप से आरएसपी प्रबंधन का आभारी हूं कि उसने शुरुआती चरण में उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे एक साइकिल चालक के रूप में विकसित होने का अवसर, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया। स्वास्ती एक मेहनती और समर्पित लड़की है, और मुझे उ मीद है कि वह देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देगी और राउरकेला को गौरवान्वित करेगी। सेल, राउरकेला इस्पात संयंत्र के पूरे समूह ने अंतराष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतिभा सु श्री स्वास्ती सिंह को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। स्वास्ती, अपनी मेहनत से कामयाबी की ओर आगे बढ़ो! आरएसपी सामूहिक और पूरा राउरकेला शहर आपके पीछे खड़ा है।